

6 अप्रैल, 2023

प्रेस विज्ञप्ति

वर्तमान विधायकों का विश्लेषण जिनके खिलाफ आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आने वाले अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए हैं।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स

टी-95, सी.एल. हाऊस, द्वितीय तल,
नज़दीक गुलमोहर कमर्शियल काम्पलेक्स,
गौतम नगर, नई दिल्ली- 110049,
फोन नं.: 011-4165 4200, फ़ैक्स नं.: 4609 4248
ईमेल: adr@adrindia.org

रिपोर्ट के मुख्य अंश

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कर्नाटक इलेक्शन वॉच ने कर्नाटक विधानसभा 2018 के **219** वर्तमान विधायकों के शपथपत्रों का विश्लेषण किया है, इन **219** में से **32 (15 प्रतिशत)** ऐसे विधायक हैं, जिनके ऊपर आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आने वाले अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए हैं। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित बातों का विश्लेषण किया गया है:

1. आपराधिक मामलों वाले विधायकों की संख्या जो आर.पी. अधिनियम की धारा 8(1) के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें दोषी ठहराए जाने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा।
2. आपराधिक मामलों वाले विधायकों की संख्या जो आर.पी. अधिनियम की धारा 8(2) के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें कम से कम 6 महीने की सजा के साथ दोषी ठहराए जाने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा।
3. आपराधिक मामलों वाले विधायकों की संख्या जो आर.पी. अधिनियम की धारा 8(3) के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें 2 साल से कम की सजा के साथ दोषी ठहराए जाने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा।

आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के बारे में:

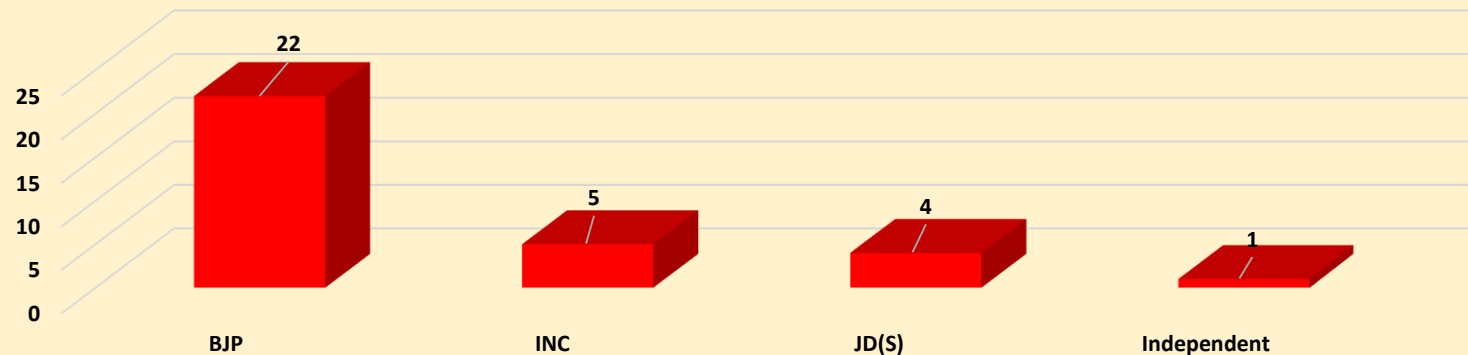
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 में राज्य में 'संसद के किसी भी सदन के सदस्य' के साथ-साथ 'विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य' के रूप में होने और चुने जाने वाले व्यक्तियों के लिए अयोग्यता का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 8 की उप-धाराएं (1), (2) और (3) में प्रावधान है कि इनमें से किसी भी उपधारा में उल्लिखित अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा और उसकी रिहाई के छह साल बाद तक की अवधि के लिए वह अयोग्य बना रहेगा।

धारा 8 (1), (2) और (3) के तहत सूचीबद्ध अपराध गंभीर/भयानक/जघन्य प्रकृति के हैं और भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) के तहत हत्या, बलात्कार, डकैती, लूट, अपहरण, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, रिश्वत, अनुचित प्रभाव, धर्म, नस्ल, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शुत्रता जैसे अपराध शामिल हैं। इसमें भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग, उत्पादन/विनिर्माण/खेती, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, और/या किसी भी नशीली दवा या मनःप्रभावी पदार्थ के सेवन से संबंधित अपराध, FERA, 1973 से संबंधित अपराध, जमाखोरी और मुनाफाखोरी से संबंधित अपराध, भोजन और दवाओं में मिलावट, दहेज आदि से संबंधित अपराध भी शामिल हैं। इसके अलावा, धारा 8 में उन सभी अपराधों को भी शामिल किया गया है जहां एक व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है।

आपराधिक मामले घोषित करने वाले विधायक दलवार जिनके ऊपर आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आरोप तय किए गए हैं।

- 32 विधायकों ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनके ऊपर आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आरोप तय किए गए हैं।
- दलों में, **BJP** के सबसे अधिक 22 विधायकों, इसके बाद **INC** के 5, **JD(S)** के 4 और **निर्दलीय** के 1 विधायकों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनके ऊपर आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आरोप तय किए गए हैं।

Party-wise Number of MLAs against whom charges have been framed by the court for offences falling under Section 8(1) (2) & (3) of the R.P Act,1951.



आलेख: विधायक दलवार जिनके ऊपर आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आने वाले अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए हैं।

दल	विधायक दलवार जिनके ऊपर आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आने वाले अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए हैं।
BJP	22
INC	5
JD(S)	4
Independent	1
कुल	32

तालिका: विधायक दलवार जिनके ऊपर आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आने वाले अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए हैं।

विधायकों के लंबित आपराधिक मामलों का विश्लेषण, जिन्होंने आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनके ऊपर आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आरोप तय किए गए हैं।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 और बाद में हुए उपचुनावों के समय विधायकों द्वारा जमा किये गए शपथपत्रों से उपलब्ध जानकारी के आधार पर आर.पी. अधिनियम की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत लंबित आपराधिक मामले जिन में आरोप तय हुए थे, उनकी जानकारी नीचे दी गई है। लेकिन ध्यान रहे कि इन मामलों में पिछले गुजरे वर्षों में कुछ बदलाव हो सकता है। इन मामलों की मौजूदा स्थिति केवल पुनः चुनाव लड़ने वाले विधायकों द्वारा आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए शपथपत्र जमा करने पर ही सही स्थिति मालूम होगी।

- 32 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित रहने की औसत संख्या 5 वर्ष है।
- 6 विधायकों के खिलाफ दस साल या उससे अधिक समय से कुल 9 आपराधिक मामले लंबित हैं।

सबसे लंबे समय से लंबित आपराधिक मामले:

16 वर्ष	14 वर्ष	11 वर्ष	10 वर्ष
<p>. Punishment of criminal conspiracy: G Somasekhara Reddy of BJP from Bellary City constituency.</p>	<p>. Punishment for Defamation, Printing or engraving matter known to be defamatory, Sale of printed or engraved substance containing defamatory matter: B Sreeramulu of BJP from Molakalmuru constituency.</p> <p>. Punishment for criminal breach of trust, Cheating and dishonestly inducing delivery of property: Ranganath H D of INC from Kunigal constituency.</p>	<p>. Punishment for criminal intimidation, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Punishment for Rioting, Rioting, armed with deadly weapon, Assault or criminal force with intent to dishonour person, otherwise than on grave provocation, Mischief causing damage to the amount of fifty rupees: Yashvanthrayagouda Patil of INC from Indi constituency.</p>	<p>. Mischief by destroying or moving, etc., a land- mark fixed by public authority Mischief by fire or explosive substance with intent to cause damage to amount of one hundred or (in case of agricultural produce) ten rupees, Joining or continuing in unlawful assembly, knowing it has been commanded to disperse, Punishment for Rioting, Mischief causing damage to the amount of fifty rupees: K.Y. Nanjegowda of INC from Malur constituency.</p> <p>. Joining or continuing in unlawful assembly, knowing it has been commanded to disperse, Rioting, Punishment for Rioting, Mischief causing damage to the amount of fifty rupees: D.C.Thammanna of JD(S) from Maddur constituency.</p>

वर्तमान विधायकों का पूर्ण विवरण जिनके ऊपर आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आने वाले अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए हैं, और जिन पर 10 से अधिक वर्षों से मामले लंबित हैं। (2018 में प्रस्तुत शपथपत्रों के अनुसार)

क्र०सं०	विधायकों का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	दल	सबसे लंबे समय से लंबित आपराधिक मामले (केवल उन विधायकों के जिनके ऊपर आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आने वाले अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए हैं।)	आईपीसी/अधिनियमों का विवरण जो विधायक के अयोग्यता का कारण बन सकता है	चुनाव वर्ष	मामला / एफआईआर वर्ष	लंबित मामलों के वर्षों की संख्या
1	G Somasekhara Reddy	Bellary City	BJP	IPC Sections - 120B, 34 , Other Details - Section 13(1)d, R/w 13(2) of Prevention of Corruptions Act, CC No 12/2002(Crime No 8/2012) By Anti- Corruption Bureau, Hyderabad Telangana State, Court Taking Cognizance-Principal Special Judge for SPE & ACB At Hyderabad, Crime No 8/12, Date of Cognizance- 09.06.2013, Court Which Framed Charge- Principal Special Judge for SPE & ACB At Hyderabad, Date of Charge Framed- 18.11.2014	1 charge related to Punishment of criminal conspiracy (IPC Section-120B)	2018	2002	16
2	B Sreeramulu	Molakalmuru	BJP	IPC Sections - 500, 501, 502, Other Details - P.C.NO. 133/2004, CC.NO. 1600/2005, Cognizance Court-1st Addl. Civil Judge JMFC Bellary, Cognizance Date- 29.07.2004, Framed Court - 1st Addl Civil Judge JMFC Bellary, Framed date -20.11.2006	1 charge related to Punishment for Defamation (IPC Section-500) 1 charge related to Printing or engraving matter known to be defamatory (IPC Section-501) 1 charge related to Sale of printed or engraved substance containing defamatory matter (IPC Section-502)	2018	2004	14
3	Ranganath H D	Kunigal	INC	IPC Sections - 406, 420, 34 , Other Details - FIR No. 201/2004, Palarivattom Police Station, Kochin, Kerala State, Court taking Cognizance- Judicial First Class Magistrate Court I Ernakulam, Cognizance date. 26.09.2005, Court which framed charge- Judicial First	1 charge related to Punishment for criminal breach of trust (IPC Section-406) 1 charge related to Cheating and dishonestly inducing delivery of property (IPC Section-420)	2018	2004	14

क्र०सं०	विधायकों का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	दल	सबसे लंबे समय से लंबित आपराधिक मामले (केवल उन विधायकों के जिनके ऊपर आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आने वाले अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए हैं।)	आईपीसी/अधिनियमों का विवरण जो विधायक के अयोग्यता का कारण बन सकता है	चुनाव वर्ष	मामला / एफआईआर वर्ष	लंबित मामलों के वर्षों की संख्या
				Class Magistrate Court I Ernakulam, CC No. 2867/05, Date of charge framed- 31.10.2005				
4	Yashvanthrayagouda Patil	Indi	INC	IPC Sections - 143, 147, 148, 336, 355, 341, 427, 504, 506, 149 , Other Details - Karnataka State, Vijayapura Dist.Indi, Indi Taluk No-16/2007 CC.No. 58/2007, Cognizance Court & Charges Framed Court: Honourable Civil Court & First Class-Indi, Charges Framed Date 13-1-2007 & No: 06, Appeal Dated on 27-11-2017.	1 charges related to Punishment for criminal intimidation (IPC Section-506) 1 charges related to Intentional insult with intent to provoke breach of the peace (IPC Section-504) 1 charges related to Punishment for Rioting (IPC Section-147) 1 charges related to Rioting, armed with deadly weapon (IPC Section-148) 1 charges related to Assault or criminal force with intent to dishonour person, otherwise than on grave provocation (IPC Section-355) 1 charge related to Mischief causing damage to the amount of fifty rupees (IPC Section-427)	2018	2007	11
5	K.Y. Nanjegowda	Malur	INC	IPC Sections - 143, 145, 147, 188, 427, 435, 149 , Other Details - Crime No. 108/2008 Malur Police Station Kolar(Dt.), Karnataka, Cognizance Court Principal JMFC at Malur CC No. 117/09, Date of cognizance 20.02.09, Court which framed the charge	1 charge related to Mischief by destroying or moving, etc., a landmark fixed by public authority Mischief by fire or explosive substance with intent to cause	2018	2008	10

इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से दी गई है। विधायकों द्वारा दी गई शपथपत्रों की जानकारी इस विश्लेषण का स्रोत है www.adrindia.org, www.myneta.info

क्र०सं०	विधायकों का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	दल	सबसे लंबे समय से लंबित आपराधिक मामले (केवल उन विधायकों के जिनके ऊपर आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आने वाले अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए हैं।)	आईपीसी/अधिनियमों का विवरण जो विधायक के अयोग्यता का कारण बन सकता है	चुनाव वर्ष	मामला / एफआईआर वर्ष	लंबित मामलों के वर्षों की संख्या
				2nd Additional C.J. and JMFC, Framed date 01.04.2016	damage to amount of one hundred or (in case of agricultural produce) ten rupees (IPC Section-435) 1 charge related to Joining or continuing in unlawful assembly, knowing it has been commanded to disperse (IPC Section-145) 1 charge related to Punishment for Rioting (IPC Section-147) 1 charge related to Mischief causing damage to the amount of fifty rupees (IPC Section-427)			
6	D.C.Thammanna	Maddur	JD(S)	IPC Sections - 143, 145, 146, 147, 323, 427, 448, 188, 149 , Other Details - Section 2(B) of Destruction and Loss of Property Act 1981, Crime No. 255/2008, FIR No. 575/2008, C.C.No. 380/2009, Mandya West Police Station, Mandya Karnataka State, Court taking Cognizance- Addl. Civil Judge (Junior Division) and JMFC Mandya, Date of Cognizance- 23.03.2009, Court which framed charge- Addl. CJM (JD & JMFC Mandya), Date of charge framed- 20.02.2018, The Complainant filed an application U/S 323 of CRPC	1 charge related to Joining or continuing in unlawful assembly, knowing it has been commanded to disperse (IPC Section-145) 1 charge related to Rioting (IPC Section-146) 1 charge related to Punishment for Rioting (IPC Section-147) 1 charge related to Mischief causing damage to the amount of fifty rupees (IPC Section-427)	2018	2008	10

तालिका: वर्तमान विधायकों का पूर्ण विवरण जिनके ऊपर आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आने वाले अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए हैं, और जिन पर 10 से अधिक वर्षों से मामले लंबित हैं।

एडीआर द्वारा अवलोकन:

- I. 10 अगस्त, 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 13 फरवरी, 2020 और 25 सितंबर, 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चुनाव लड़ने वाले 10 राजनीतिक दलों को दंडित किया, जिन्होंने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित अपनी वेबसाइट पर 72 घंटों के भीतर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन करने के कारणों को सूचीबद्ध करें। नरम रुख अपनाते हुए, राजनीतिक दलों पर, ₹ 1 लाख से 5 लाख का जुर्माना लगाया गया क्योंकि राजनीतिक दल सर्वोच्च न्यायालय और अन्य मुख्य हितधारकों के बार-बार याद दिलाने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने में विफल रहे थे। वास्तव में, चुनाव जीतने के अपने एकमात्र उद्देश्य के साथ, राजनीतिक दलों ने जानबूझकर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले ऐसे दागी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और प्रतिभा, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, योग्यता और उपलब्धियों जैसे सहभागी लोकतंत्र में आवश्यक महत्वपूर्ण साख की अनदेखी की गई थी।
- II. 10 अगस्त, 2021 का आदेश स्पष्ट रूप से इंगित करता है, कि न तो 'विधायिका और न ही 'राजनीतिक दल कभी भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में 'बाहुबली' उम्मीदवारों के प्रवेश को रोकने के लिए कदम उठाने के इच्छुक होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 10 अगस्त, 2021 को अपने आदेश में दुखद रूप से कहा था, "इस न्यायालय ने बार-बार देश के कानून निर्माताओं से अपील की है कि वे इस मुद्दे पर आवश्यक संशोधन लाने के लिए कदम उठाएं ताकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की राजनीति में भागीदारी प्रतिबंधित हो। ये सभी अपीलें ठंडे बस्ते में पड़ी हैं।"
- III. राजनीति में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में छह आदेश दिए हैं; 10 मार्च, 2014 (एक वर्ष के भीतर परीक्षण); 27 अगस्त, 2014 (प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मंत्रियों को नियुक्त नहीं करने का विशेषाधिकार) 1 नवंबर, 2017 (विशेष 11 फास्ट-ट्रैक कोर्ट); 25 सितंबर, 2018 (आपराधिक मामलों का प्रकाशन); 13 फरवरी, 2020 (आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को टिकट देने का कारण), 10 अगस्त, 2021 (सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करने पर राजनीतिक दलों को दंड)। दुर्भाग्य से, इनमें से कोई भी आदेश पार्टियों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से नहीं रोक पाया है। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, "राष्ट्र इस तरह के कानून का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि समाज को उचित संवैधानिक शासन द्वारा शासित होने की एक वैध उम्मीद है। जब धनबली और बाहुबली सर्वोच्च शक्ति बन जाता है तो देश को पीड़ा होती है।"

- IV. कानून में यह कमी जनहित के लिए हानिकारक है। न्यायपालिका द्वारा कठोर कार्रवाई और उपाय किए जाने की आवश्यकता है। केवल चेतावनी या मामूली जुर्माना लगाने से चुनाव से आपराधिक तत्वों को खत्म करने में मदद नहीं मिलेगी। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि सुधारों को हमारे नेताओं और राजनीतिक दलों के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए, यह समय की आवश्यकता है कि सर्वोच्च न्यायालय हमारे कानून निर्माताओं द्वारा जानबूझकर खाली छोड़े गए क्षेत्र में कदम उठाए और हमारी चुनावी और राजनीतिक प्रक्रिया से ऐसे तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाने वाले निर्देश लाए।
- V. अब समय आ गया है कि न्यायालय इस विश्वास को खत्म कर दें कि 'आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता उनकी शक्तियों के दायरे से बाहर है।' 'शक्तियों का विभाजन' सिद्धांत एक सहवर्ती सिद्धांत है जिसे 'नियंत्रण और संतुलन' कहा जाता है। जबकि संघीय ढांचे का प्रत्येक स्तंभ अपने कार्यों को अभ्यास में स्वतंत्र है, हालांकि, यदि कोई एक स्तंभ वह नहीं करता है जो उसे करना चाहिए या कुछ गलत करता है, अन्य दो स्तंभों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक स्तंभ की अक्षमता या अनिच्छा से उत्पन्न होने वाली विकृतियों को ठीक करने के लिए कदम उठाएँ जैसा कि संविधान में दर्शाया गया है। निहितार्थ यह है कि प्रत्येक स्तंभ का अधिकार स्वतंत्र है, लेकिन यह निरपेक्ष नहीं है। यह अन्य दो स्तंभों द्वारा 'नियंत्रित और संतुलित' होने के अधीन है।

एडीआर द्वारा सिफारिशें

सुशासन केवल अच्छे लोगों के हाथ में होता है। राजनीतिक में आपराधिकता की बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाने के लिए समाधानों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो इसे करने की हिम्मत और इच्छाशक्ति की। केवल ईमानदार, निष्पक्ष, विश्वसनीय, सक्षम और चरित्रवान और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों को ही चुनाव लड़ना चाहिए और प्रमुख नीति निर्माता बनना चाहिए।

1999 की कई समितियों द्वारा दी गई विभिन्न सिफारिशें ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं। एडीआर दृढ़ता से महसूस करता है कि यदि (a) कानून में कोई अंतर, शून्यता या दुर्बलता है, (b) विधायिका और कार्यपालिका के पास अंतराल को भरने या दुर्बलता को ठीक करने का समय नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, (c) जनहित पीड़ित है, तो न्यायपालिका को न केवल अधिकार है, बल्कि यह उसका कर्तव्य भी है कि वह इस कमी को पूरा करे और इस कमी को दूर करे।

इसलिए, एडीआर निम्नलिखित सिफारिशों का दृढ़ता से महसूस करता है और उनका समर्थन करता है, कि हमारे सहभागी लोकतंत्र और कानून के शासन को नुकसान पहुंचाने वालों पर बिना किसी देरी के तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।

- I. **‘अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों’ पर अयोग्यता:** अपराधीकरण की समस्या से निपटा जा सकता है यदि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को अपराध के चरण और डिग्री दोनों के आधार पर चुनावी प्रक्रिया में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह उन उम्मीदवारों को सार्वजनिक कार्यालयों में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करके प्राप्त किया जा सकता है जिनके खिलाफ न्यायालय द्वारा कम से कम 5 वर्ष के कारावास के अपराधों के आरोप लगे हैं और जो मामला चुनाव से कम से कम 6 महीने पहले दायर किया गया है।
- II. **जघन्य अपराधों के लिए स्थायी अयोग्यता:** हमारे और इस देश के लिए कानून बनाना और देश के लिए नीतियां बनाने वाले कानून निर्माताओं पर जघन्य अपराधों का आरोप लगाना या उन्हें दोषी ठहराना निंदनीय है। हत्या, बलात्कार, तस्करी, डकैती, अपहरण, लूट आदि जैसे जघन्य अपराधों के लिए दोषी उम्मीदवारों को स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।

- III. उम्मीदवारों के चयन के लिए मापदंड:** राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के चयन के लिए एक सख्त मापदंड होना चाहिए। 13 फरवरी, 2020 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, राजनीतिक दलों को पहले से ही उम्मीदवारों के चयन के लिए कारण बताने की आवश्यकता है और साफ छवि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है। निर्णय के अनुसार ऐसे चयन का कारण संबंधित उम्मीदवार की उपलब्धियों और योग्यता के संदर्भ में होना चाहिए और न की उसकी चुनाव "जीतने" की क्षमता।
- IV. किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी द्वारा आपराधिक मामलों पर वार्षिक सूचना दाखिल करना:** राजनीतिक दल को अपने पदाधिकारियों जैसे अध्यक्ष, सचिव, महासचिव, संयोजक, कोषाध्यक्ष आदि के आपराधिक मामलों की जानकारी सालाना दर्ज करनी चाहिए और इस तरह के आंकड़े जनता के लिए उपलब्ध कराने चाहिए, जिसमें शून्य वाले मामले भी शामिल हों।
- V. विधायकों/सांसदों के न्यायालय में लंबित मामलों की फास्ट ट्रैकिंग:** सांसदों और विधायकों के खिलाफ सभी लंबित मामलों को तेजी से ट्रैक किया जाना चाहिए और 10 मार्च, 2014 और 1 नवंबर, 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार एक वर्ष की अवधि के भीतर निष्कर्ष पर लाया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि सीआरपीसी की धारा 321 के तहत दी गई ऐसी बेलगाम और मनमानी शक्ति का सरकारों द्वारा शक्तिशाली राजनेताओं, मंत्रियों और अन्य अमीर और शक्तिशाली लोगों के खिलाफ लंबित मामलों को वापस लेने को आदेश देकर दुरुपयोग तो नहीं किया जाता है।
- VI. चुनाव आयोग द्वारा तैयार और साझा किए जाने वाले राजनीतिक दलों की सूचि:** भारत के चुनाव आयोग से 25 सितंबर, 2018, 13 फरवरी, 2020 और 10 अगस्त, 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अपने पत्र में लागू करने की उम्मीद है, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा चुने गए ऐसे दागी उम्मीदवारों के नाम और चयन के कारणों को सूचीबद्ध करना होगा। इस सूचि को हर चुनाव के बाद सही रूप से तैयार कर सर्वोच्च न्यायालय में जमा करने की जरूरत है और इसे सार्वजनिक निरीक्षण के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए।
- VII. राजनीतिक दलों को अमान्य करना:** सर्वोच्च न्यायालय के 25 सितंबर, 2018, 13 फरवरी, 2020 और 10 अगस्त, 2021 के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अनुच्छेद 16 A के तहत एक गंभीर उल्लंघन माना जाना चाहिए। अनुच्छेद 16 A आयोग को आदर्श आचार संहिता का पालन न करने या आयोग के वैध आदेशों और निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता को निलंबित करने या वापस लेने का भी अधिकार है। इसलिए, भारत के चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ अनुच्छेद 16 A के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग

करना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की लगातार विफलता और अवज्ञा के लिए किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता को निलंबित या वापस लेना चाहिए।

- VIII. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की पूर्व घोषणा:** चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची चुनाव से कम से कम 3 महीने पहले घोषित की जानी चाहिए और उन्हें किसी विशेष पार्टी को बदलने/शामिल होने और अगले चुनाव में उनके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि और उसके स्रोत के बारे में विशेष कारण बताते हुए शपथपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। यह सभी जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में लाई जानी चाहिए।
- IX. उल्लंघन के लिए पार्टियों को परिणाम भुगतने होंगे:** राजनीतिक दलों को यह महसूस करना चाहिए कि विभिन्न हितधारकों द्वारा ईमानदार, विश्वसनीय उम्मीदवारों के चयन करने की अपील; नागरिक, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय के लिए अनिवार्य हैं और इसलिए अनुपालन वैकल्पिक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के 25 सितंबर, 2018, 13 फरवरी, 2020 और 10 अगस्त, 2021 के आदेश की खुलेआम अवहेलना करने के लिए पार्टियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अपर्याप्त प्रकटीकरण, अमान्य और सामान्य कारणों, जीत के आधार पर उम्मीदवारों का चयन, समय पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने आदि के लिए उन पर भारी वित्तीय दंड लगाया जाना चाहिए। अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित एक राजनीतिक दल के प्रभारी अधिकारी को भी इस तरह के उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
- X. राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र के लिए प्रावधानों का परिचय दें:** दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक होने के बावजूद, हमारे राजनीतिक दलों का कामकाज करने का तरीका बहुत अलोकतांत्रिक है। राजनीतिक दल अपने 'आचार संहिता' और स्वयं के लिए शुरू किए गए सुधार में बुरी तरह से विफल रहे हैं। इसलिए राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शी निर्णय लेने, टिकट वितरण, पदाधिकारियों के चुनाव, वित्तीय पारदर्शिता और मजबूत संगठनात्मक अनुशासन को लागू करने के लिए अनिवार्य प्रावधान किए जाने चाहिए। इसमें सभी आंतरिक पार्टी पदों और उम्मीदवारों के चयन के लिए सभी चुनावों के लिए गुप्त बैलेट मतदान अनिवार्य होना चाहिए, जैसा कि 170वें विधि आयोग की रिपोर्ट द्वारा सुझाया गया है।
- XI. नोटा को अधिक शक्ति:** 23 सितंबर, 2013 को सर्वोच्च न्यायालय के नोटा के फैसले पर अगला कदम उठाना आवश्यक है। (a) यदि नोटा को किसी भी उम्मीदवार की तुलना में अधिक वोट मिलते हैं, तो किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित नहीं किया जाना चाहिए, और दुबारा चुनाव होने चाहिए; (b) यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी उम्मीदवारों को नोटा से कम वोट मिलते हैं तो उन्हें दुबारा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

- XII. राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में घोषित किया जाए:** आरटीआई कानून के तहत पार्टियों को लाने से नागरिकों को न केवल आंतरिक पार्टी चुनाव, टिकट वितरण के मापदंड जैसी जानकारी, ऑडिट, समीक्षा, जांच और आंकलन का अधिकार होगा, बल्कि लोगों को हमारे राजनीतिक दलों द्वारा मैदान में उतारे जाने वाले उम्मीदवारों के लिए पदाधिकारियों से निश्चित और सीधा जवाब लेने की भी अनुमति देगा। इसलिए, यह उचित समय है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस वर्तमान स्थिति पर ध्यान दे और पार्टियों को आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाकर 3 जून, 2013 सीआईसी के आदेश को लागू करे।
- XIII. राजनीतिक दलों के मामलों को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता:** राजनीतिक दल हमारे संवैधानिक, लोकतांत्रिक, सामाजिक-आर्थिक गठन के अंतिम भंडार और संरक्षक हैं, लेकिन हमारे पास राजनीतिक दलों से पूरी तरह से निपटने वाला एक भी व्यापक कानून नहीं है। एक व्यापक कानून के अभाव में, नागरिक राजनीतिक वर्ग और राजनेताओं के कामकाज पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, उनका मूल्यांकन और ऑडिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए, राजनीतिक दलों के कामकाज को विनियमित करने, उनकी पार्टी के संविधान की मान्यता, पार्टी के अंगों के विभिन्न स्तरों पर चुनाव, पंजीकरण और गैर-पंजीकरण की शर्तों, खातों के अनिवार्य रखरखाव, संगठनात्मक पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानून की सख्त आवश्यकता है। यह प्रावधान '170वें विधि आयोग की रिपोर्ट, भाग 3, अध्याय 1' और NCRW रिपोर्ट के अध्याय 8 में अनुशंसित है।
- XIV. झूठे शपथपत्रों को तत्काल अयोग्यता का कारण बनना चाहिए:** उम्मीदवारों द्वारा शपथपत्रों में गलत जानकारी देना चुनाव आयोग द्वारा हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। आखिरकार, यह 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आरपीए अधिनियम, 1951 की धारा 125A उम्मीदवारों को गलत/झूठी जानकारी प्रस्तुत करने से नहीं रोक पाई है क्योंकि इसमें केवल 6 महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है, और इसलिए अयोग्यता को आकर्षित नहीं करता है। चुनावी शपथपत्रों में गलत जानकारी, कोई जानकारी न देना, झूठी जानकारी देने वाले उम्मीदवारों को तत्काल अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।
- XV. फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट, "पंजीकृत मतों का 50 प्रतिशत + 1":** कानून आयोग, NCRW, जैसी विभिन्न समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार 'किसी भी उम्मीदवार को तब तक निर्वाचित घोषित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह 50 प्रतिशत से अधिक मत हासिल नहीं कर लेता।' जब किसी उम्मीदवार को मतदाताओं की आवश्यक संख्या नहीं मिलती है, तो शीर्ष दो उम्मीदवारों के बीच अधिकतम वोट पाने के लिए स्पर्धा होनी चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि डाले गए वोटों का 50 प्रतिशत + 1 निर्वाचित घोषित करने के लिए एक आसान आवश्यकता है, एक अधिक कठोर आवश्यकता और उपयुक्त और उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आदर्श है।

XVI. सांसदों और विधायकों की वार्षिक रिपोर्ट: निर्वाचित सांसदों और विधायकों को पिछले वर्ष की अपनी उपलब्धियों और अगले वर्ष की योजना का विवरण देते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक 'वार्षिक रिपोर्ट' प्रस्तुत करने की आवश्यकता होनी चाहिए। यह रिपोर्ट लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभा की वेबसाइट और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

विधायकों के घोषित आपराधिक मामलों का पूर्ण विवरण, जिन्होंने आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनके ऊपर आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) (2) और (3) के तहत आरोप तय किए गए हैं। (2018 में प्रस्तुत शपथपत्रों के अनुसार)

क्र०सं०	विधायकों का विवरण	आईपीसी का संक्षिप्त विवरण/अधिनियमों का विवरण जो विधायक के अयोग्यता का कारण बन सकता है
1	<p>Name:M P Renukacharya District: Davangere Constituency: Honnali Party:BJP Cases (Charges Framed)</p> <p>1. IPC Sections - 171E , Other Details - Shimoga police station crime no-178/13, cognizance court 3rd JMFC court shimoga, C.C.No-1536/13 Charges framed Date- 09-11-2015</p>	<p>1 charge related to Punishment for bribery (IPC Section-171E)</p>
2	<p>Name:Abhayakumar Patil District: Belgaum Constituency: Belgaum Dakshin Party:BJP Cases (Charges Framed)</p> <p>1. IPC Sections - 143, 147, 148, 109, 117, 353, 332, 114, 324, 427, 504, 506, 149 , Other Details - Section 2(a) KPDP Act, CC No. 421/2011, FIR No. 66/2011, Police Station- Shahapur, Tal. Dist.- Belagavi (Karnataka), Court taking Cognizance- IIIrd Addl. JMFC Belagavi, Date of Cognizance- 02.07.2011 for Section 153A 20.07.2013, Court which framed charge- IIIrd Addl. JMFC Belagavi, Date of charge framed- 15.12.2012</p> <p>2. IPC Sections - 143, 147, 148, 448, 427, 109, 119, 117, 114, 504, 506, 149 , Other Details - Section 2(a) KPDP Act, CC No. 422/2011, FIR No. 67/2011, Police Station- Shahapur, Tal. Dist.- Belagavi (Karnataka), Court taking Cognizance- IIIrd Addl. JMFC Belagavi, Date of Cognizance- 04.02.2011 for Section 153A 20.07.2013, Court which framed charge- IIIrd Addl. JMFC Belagavi, Date of charge framed- 15.12.2012</p>	<p>2 charges related to Punishment for criminal intimidation (IPC Section-506) 1 charges related to Punishment for bribery (IPC Section-171E) 1 charge related to Voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty (IPC Section-332) 1 charge related to Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means (IPC Section-324) 1 charge related to Public servant concealing design to commit offence which it is his duty to prevent (IPC Section-119) 2 charges related to Intentional insult with intent to provoke breach of the peace (IPC Section-504) 2 charges related to Punishment for Rioting (IPC Section-147) 2 charges related to Rioting, armed with deadly weapon (IPC Section-148) 2 charges related to Punishment of abetment if the act abetted is committed in consequence, and where no express provision is made for its punishment (IPC Section-109) 2 charges related to Abetting commission of offence by the public or by more than ten persons (IPC Section-117) 2 charges related to Abettor present when offence is committed (IPC Section-114) 2 charges related to Mischief causing damage to the amount of fifty rupees (IPC Section-427) 1 charge related to Assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty (IPC Section-353)</p>

क्र०सं०	विधायकों का विवरण	आईपीसी का संक्षिप्त विवरण/अधिनियमों का विवरण जो विधायक के अयोग्यता का कारण बन सकता है
	3. IPC Sections - 171B, 171E, 188 , Other Details - CC No. 452/2013, FIR No. 49/2013, Police Station- Shahapur, Tal. Dist.- Belagavi (Karnataka), Court taking Cognizance- Illrd Adl. JMFC Belagavi, Date of Cognizance- 14.05.2013, Court which framed charge- Illrd Adl. JMFC Belagavi, Date of charge framed- 10.07.2015	
3	<p>Name:Veerabhadrayya (veeranna) Charantimath District: Bagalkot Constituency: Bagalkot Party:BJP Cases (Charges Framed)</p> <p>1. IPC Sections - 323, 324, 342, 504, 506, 34 , Other Details - CC.No.1649/13, Crime No.87/13, Police Station-Bagalkot Town P.S. Dist Bagalkot Karnataka State, Court Which Framed The Charge 1 Adl.Civil Judge and JMFC Court Bagalkot, Framed Dt.12.11.2014, Court Taking Cognizance 1 Adl. Civil Judge and JMFC Court Bagalkot. Taken Cognizance, Date of Cognizance 21.12.2013</p>	<p>1 charge related to Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means (IPC Section-324) 1 charge related to Punishment for criminal intimidation (IPC Section-506) 1 charge related to Intentional insult with intent to provoke breach of the peace (IPC Section-504)</p>
4	<p>Name:Basanagoud Patil District: Bijapur Constituency: Bijapur City Party:BJP Cases (Charges Framed)</p> <p>1. IPC Sections - 109, 114, 120(B), 149, 205, 207, 420, 423, 467, 478, 471, 480 , Other Details - CC No. 628/2013, Cognizance Court-JMFC-3, Vijaypur, Cgnizance Date- 04.05.2013, Framed Court-JMFC-3 Vijaypur, Framed Date-04-05-2013 2. IPC Sections - 109, 114, 120(B), 149, 205, 207, 420, 423, 467, 478, 471, 480 , Other Details - CC No. 636/2013, Cognizance Court-JMFC-3, Vijaypur, Cgnizance Date- 04.05.2013, Framed Court-JMFC-3 Vijaypur, Framed Date-04-05-2013</p>	<p>2 charges related to Cheating and dishonestly inducing delivery of property (IPC Section-420) 2 charges related to Forgery of valuable security, will, etc. (IPC Section-467) 2 charges related to Punishment of abetment if the act abetted is committed in consequence, and where no express provision is made for its punishment (IPC Section-109) 2 charges related to Abettor present when offence is committed (IPC Section-114) 2 charges related to Punishment of criminal conspiracy (IPC Section-120B) 2 charges related to False personation for purpose of act or proceeding in suit or prosecution (IPC Section-205) 2 charges related to Fraudulent claim to property to prevent its seizure as forfeited or in execution (IPC Section-207) 2 charges related to Dishonest or fraudulent execution of deed of transfer containing false statement of consideration (IPC Section-423) 2 charges related to Using as genuine a forged document or electronic record (IPC Section-471)</p>
5	<p>Name:Basavaraj Durugappa Dadesugur District: Koppal Constituency: Kanakagiri</p>	<p>1 charge related to Punishment for Rioting (IPC Section-147) 1 charge related to Assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty (IPC Section-353)</p>

क्र०सं०	विधायकों का विवरण	आईपीसी का संक्षिप्त विवरण/अधिनियमों का विवरण जो विधायक के अयोग्यता का कारण बन सकता है
	<p>Party:BJP Cases (Charges Framed)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IPC Sections - 143, 147, 341, 186, 283, 353, 323, 109 , Other Details - FIR No.137\15, C.C.No.825\16, P.S.-Karatagi, Court taknig Cognizance-Prl Civil Judge & JMFC Gangavati, Charge Framed Court-Prl Civil Judge & JMFC Gangavati, Framed Date-13-7-2016 2. IPC Sections - , Other Details - CC No.512/14, Kopal Police Station, Cognizance Court-Sr. Civil Judge & CJM, Kopal, Charge Framed Court-Sr. Civil Judge & CJM, Kopal, Framed Date-11-4-2014 3. IPC Sections - , Other Details - FIR No.162/13, CC No-286/14, Cognizance Court-Sr. Civil Judge & CJM, Kopal, Charge Framed Court-Sr. Civil Judge & CJM, Kopal, Framed Date-18-7-2014 	<p>1 charge related to Punishment of abetment if the act abetted is committed in consequence, and where no express provision is made for its punishment (IPC Section-109)</p>
6	<p>Name:Parappa M. Ishwarappa Munavalli District: Koppal Constituency: Gangavathi Party:BJP Cases (Charges Framed)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IPC Sections - 143, 147, 341, 109, 149 , Other Details - CITY POLICE STATION, KOPAL, KARNATAKA, CR.No.162/2013, COURT TAKING COGNIZANCE-HONORABLE CITY & SESSION COURT, KOPPAL, C.C.NO-286/2014, CHARGE FRAMED COURT-HONORABLE CITY & SESSION COURT, KOPPAL, FRAMED DATE-2014 	<p>1 charge related to Punishment for Rioting (IPC Section-147) 1 charge related to Punishment of abetment if the act abetted is committed in consequence, and where no express provision is made for its punishment (IPC Section-109)</p>
7	<p>Name:G Somasekhara Reddy District: Bellary Constituency: Bellary City Party:BJP Cases (Charges Framed)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IPC Sections - 120B, 34 , Other Details - Section 13(1)d, R/w 13(2) of Prevention of Corruptions Act, CC No 12/2002(Crime No 8/2012) By Anti Corruption Bureau, 	<p>1 charges related to Punishment of criminal conspiracy (IPC Section-120B)</p>

क्र०सं०	विधायकों का विवरण	आईपीसी का संक्षिप्त विवरण/अधिनियमों का विवरण जो विधायक के अयोग्यता का कारण बन सकता है
	Hyderabad Telngana State, Court Taking Cognizance-Principal Special Judge for SPE & ACB At Hyderabad, Crime No 8/12, Date of Cognizance- 09.06.2013, Court Which Framed Charge- Principal Special Judge for SPE & ACB At Hyderabad, Date of Charge Framed- 18.11.2014	
8	<p>Name:B Sreeramulu District: Chitradurga Constituency: Molakalmuru Party:BJP Cases (Charges Framed)</p> <p>1. IPC Sections - 500, 501, 502 , Other Details - P.C.NO. 133/2004, CC.NO. 1600/2005, Cognizance Court-1st Addl. Civil Judge JMFC Bellary, Cognizance Date-29.07.2004, Framed Court - 1st Addl Civil Judge JMFC Bellary, Framed date -20.11.2006</p>	<p>1 charge related to Punishment for Defamation (IPC Section-500) 1 charge related to Printing or engraving matter known to be defamatory (IPC Section-501) 1 charge related to Sale of printed or engraved substance containing defamatory matter (IPC Section-502)</p>
9	<p>Name:K Madalu Virupakshappa District: Davangere Constituency: Channagiri Party:BJP Cases (Charges Framed)</p> <p>1. IPC Sections - 198, 104 , Other Details - 8&9 PC Act., 1998, PCR no 19/2013, CR no 28/2013, Court taking cognizance:- District session judicial Davanagre, Cognizance date. 11/6/2013, charge framed court :- District session judicial Davnagare, charge framed date. 11/6/2013</p>	<p>1 charge related to Using as true a certificate known to be false (IPC Section-198)</p>
10	<p>Name:C T Ravi District: Chikmagalur Constituency: Chickamagalur Party:BJP Cases (Charges Framed)</p>	<p>1 charge related to Criminal breach of trust by public servant, or by banker, merchant or agent (IPC Section-409) 1 charge related to Cheating and dishonestly inducing delivery of property (IPC Section-420) 1 charge related to Forgery of record of court or of public register, etc. (IPC Section-466) 1 charge related to Punishment for bribery (IPC Section-171E)</p>

क्र०सं०	विधायकों का विवरण	आईपीसी का संक्षिप्त विवरण/अधिनियमों का विवरण जो विधायक के अयोग्यता का कारण बन सकता है
	<ol style="list-style-type: none"> 1. IPC Sections - 409, 420, 120, 463, 466, 120B , Other Details - Sec 08,12,13(1) C & D Prevention of Corruption Act, Case no 114/12, Cognizance Court - Aditonal Dist Session Court Mahoyo Hall [Special Lokayuktha Court][C C H 78] Bangalore, Cognizance Date 14-06-2012 , Charges Framed Court - Aditonal Dist Session Court Mahoyo Hall [special lokayuktha court][C C H 78] Charges Framed Date 14-6-2012 , Appeal filed - criminal revision no 4749/2012 at Karnataka high court Case no 114/12 2. IPC Sections - , Other Details - sec. 13(1)(E)&13(2) Prevention of Corruption Act, Case no 33/12, cognizance court - Aditonal Dist Session Court Mahoyo hall [special lokayuktha court][C C H 78] Bangalore, cognizance date 28-05-2012 , charges framed court - Aditonal Dist Session court mahoyo hall [special lokayuktha court][C C H 78] Charges Framed date 28-05-2012, Appeal filed-Criminal revision no 62671/2016 Karnataka High court case no 33/12 3. IPC Sections - 171E , Other Details - Case no 545/13, Cognizance Court - 2nd Grade civil judge and JMFC chickmangalore, cognizance date 04-05-2013, postponed to 26-07-2013,charges framed court 2nd grade civil judge and JMFC chickmangalore Charges framed date 04-05-2013 postponed to 26-07-2017 	<p>1 charge related to Forgery (IPC Section-463) 1 charge related to Punishment of criminal conspiracy (IPC Section-120B)</p>
11	<p>Name:S A Ramadas District: Mysore Constituency: Krishnaraja Party:BJP Cases (Charges Framed)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IPC Sections - , Other Details - Cr.PC 397, Appeal preferred by complainant on CC 50/2008, CRL.R.P. No. 112/2017, Cognizance Court & Court which frame the charge PRL. District and Sessions Judge, in the court of VII Addl. District and Sessions Judge, CRL.R.P- Criminal Revision Petitions No. 112/2017 2. IPC Sections - 417, 307, 506, 34 , Other Details - CC No. 21/2014, Cognizance Court & Court which framed the charge III Judicial Magistrate First Class 3. IPC Sections - 309 , Other Details - CC No. 751/2015, Cognizance Court & Court which framed the charge 1st Additional I Civil Judge and JMFC 	<p>1 charge related to Attempt to murder (IPC Section-307) 1 charge related to Punishment for criminal intimidation (IPC Section-506)</p>

क्र०सं०	विधायकों का विवरण	आईपीसी का संक्षिप्त विवरण/अधिनियमों का विवरण जो विधायक के अयोग्यता का कारण बन सकता है
12	<p>Name:Doddanagouda G Patil District: Bagalkot Constituency: Hungund Party:BJP Cases (Charges Framed)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IPC Sections - 171F , Other Details - RP ACT 130 ,FIR NO 151/2017,CC NO 1362/17 Hanagunda police station Cognizance Court - J.M.F.C Hungund, Cognizance date 06-12-2017, CHARGES FRAMED COURT J.M.F.C Hungund 2. IPC Sections - 171F , Other Details - FIR NO 116/2016,CC NO 556/16 Hangunda police station, COGNIZANCE COURT - J.M.F.C COURT Hungund, COGNIZANCE DATE 23-9-2016, CHARGES FRAMED COURT- J.M.F.C COURT Hungund, 3. IPC Sections - 171H , Other Details - FIR NO 66/2013 CC NO 590/13 Ilakallu police station COGNIZANCE COURT - J.M.F.C COURT HUNGUND, COGNIZANCE DATE 24-09-2013 CHARGES FRAMED COURT J.M.F.C HUNGUND, Criminal Revision Appeal Filed - at High Court Dharwad Appeal no.2631/2014 dated 30-06-2014 4. IPC Sections - 171H,171E , Other Details - SEC.122 & 24A APMC ACT, FIR NO.3/2017, CC NO.751/17, COGNIZANCE COURT- JMFC COURT HUNGUND, COGNIZANCE DATE -20-07-2017, CHARGES FRAMED COURT- JMFC COURT HUNGUND, CRIMINAL REVISION APPEAL FILED - C.P. NO 101648/2017 STAY FROM HIGH COURT 5. IPC Sections - 171F , Other Details - 130 RP ACT NO 104/2016 CC NO 529/16 Ilikal police station, Cognizance Court- J.M.F.C COURT HUNGUND, COGNIZANCE DATE 20/9/2016 , CHARGES FRAMED COURT- JMFC HUNGUND 6. IPC Sections - 171H , Other Details - CRIME NO 80/2018, ILKAL Police Station, Cognizance Court- JMFC Hungund, Charges framed Court- JMFC Hungund 	<p>3 charges related to Punishment for undue influence or personation at an election (IPC Section-171F) 1 charge related to Punishment for bribery (IPC Section-171E)</p>
13	<p>Name:Rajkumar District: Gulbarga Constituency: Sedam Party:BJP Cases (Charges Framed)</p>	<p>1 charge related to Cheating and dishonestly inducing delivery of property (IPC Section-420) 1 charge related to Forgery for purpose of cheating (IPC Section-468) 1 charge related to Punishment of criminal conspiracy (IPC Section-120B) 1 charge related to Punishment for forgery (IPC Section-465) 1 charge related to Using as genuine a forged document or electronic record (IPC Section-471)</p>

क्र०सं०	विधायकों का विवरण	आईपीसी का संक्षिप्त विवरण/अधिनियमों का विवरण जो विधायक के अयोग्यता का कारण बन सकता है
	<p>1. IPC Sections - 120B, 420, 465, 468, 471, , Other Details - Sec.13(2) R/w 13(1)D of PC Act 1988, FIR No.-RC1(E)2011, C.B.I. Bangalore, Karanataka, Sp.CC.No.-27/13, Court taking Cognizance-In The Court of Hon'ble 4th Additional District & Special Judge for CBI Cases Dharwad, Cognizance Date-30-03-2012, Framed Court-CBI Court Dharwad, Framed Date-30-03-2012</p>	
14	<p>Name:Harish Poonja District: Dakshina Kannada Constituency: Belthangady Party:BJP Cases (Charges Framed)</p> <p>1. IPC Sections - 143, 147, 148, 353, 504, 427, 188, 308, 149 , Other Details - Sec.- 2(A) Of Karnataka Prevention of Destruction and Loss of Property Act 1981, Bantkala Police Station, Crime NO-178/2017, Cognizance Court-JMFC, Bantvala, The case no. is not mention in the charge sheet but the case is on investigation, The Karantaka High Court issued the stay order for the Crime No.178/2007, Petition No.33635/2017(GM-RES) and 33834-33837/2017</p> <p>2. IPC Sections - 143, 147, 148, 353, 332, 429, 149 , Other Details - Sec.2(A1) of Karnataka Prevention of Destruction and Loss Property Act 1981, Bantvala City Police Station, Crime NO- 179/2017, Cognizance Court-JMFC, Bantvala, The case no. is not mention in the charge sheet but the case is on investigation</p>	<p>1 charge related to Attempt to commit culpable homicide (IPC Section-308) 1 charge related to Voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty (IPC Section-332) 1 charge related to Mischief by killing or maiming cattle, etc., of any value or any animal of the value of fifty rupees (IPC Section-429) 2 charges related to Punishment for Rioting (IPC Section-147) 2 charges related to Rioting, armed with deadly weapon (IPC Section-148) 2 charges related to Assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty (IPC Section-353) 1 charge related to Intentional insult with intent to provoke breach of the peace (IPC Section-504) 1 charge related to Mischief causing damage to the amount of fifty rupees (IPC Section-427)</p>
15	<p>Name:Sanjeeva Matandoor District: Dakshina Kannada Constituency: Puttur Party:BJP Total Cases:2 Serious IPC:2 Other IPC:10 Cases (Charges Framed)</p>	<p>1 charge related to Punishment for criminal intimidation (IPC Section-506) 1 charge related to Promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony (IPC Section-153A) 1 charge related to Punishment for Rioting (IPC Section-147) 1 charge related to Rioting, armed with deadly weapon (IPC Section-148) 1 charge related to Intentional insult with intent to provoke breach of the peace (IPC Section-504)</p>

क्र०सं०	विधायकों का विवरण	आईपीसी का संक्षिप्त विवरण/अधिनियमों का विवरण जो विधायक के अयोग्यता का कारण बन सकता है
	<p>1. IPC Sections - 143,147,148,447,504, 506, 153A,149 , Other Details - Cr.No-39/2015,Cr.Date- 19-1-2015, C.C.NO- 410/2016,Cognizance Court- A.C.J AND J.M.F.C PUTTUR, Cognizance Date- 25-02-2016, Charged Frame Court- A.C.J AND J.M.F.C PUTTUR, Charged date- 25-02-2016, Police Station Name- Uppinangadi , Dakshina kannada Dist, karnataka</p>	
16	<p>Name:N Mahesh District: Chamarajnaragar Constituency: Kollegal Party:BJP Cases (Charges Framed)</p> <p>1. IPC Sections - 143,144,145,341,353,149 , Other Details - FIR NO.211/2016 CC NO.341/2017, POLICE STATION.CHAMARAJNAGAR DIST, KOLLEGALA VILLAGE POLICE STAION COGNIZANCE COURT J M F C COURT KOLLEGALA, CHARGES FRAMED COURT.J M F C COURT KOLLEGALA , CHARGES FRAMED DATE.8-9-2016</p>	<p>1 charge related to Joining unlawful assembly armed with deadly weapon (IPC Section-144) 1 charge related to Joining or continuing in unlawful assembly, knowing it has been commanded to disperse (IPC Section-145) 1 charge related to Assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty (IPC Section-353)</p>
17	<p>Name:J C Madhuswamy District: Tumkur Constituency: Chikkayakanhalli Party:BJP Cases (Charges Framed)</p> <p>1. IPC Sections - 143,147,427,504,506,149 , Other Details - Sec.3 prevention of public property damage act 1984 s CR No 101/2017, cc no 794/2017, Court Taking cognizance:- JMFC Court, Charge framed court:- JMFC, Charge Framed Date.20-9-2017, Criminal Revision Appeal filed - Stay Order in High Court</p>	<p>1 charge related to Punishment for criminal intimidation (IPC Section-506) 1 charge related to Punishment for Rioting (IPC Section-147) 1 charge related to Mischief causing damage to the amount of fifty rupees (IPC Section-427) 1 charge related to Intentional insult with intent to provoke breach of the peace (IPC Section-504)</p>
18	<p>Name:Neharu Olekar District: Haveri Constituency: Haveri</p>	<p>2 charges related to Punishment for criminal intimidation (IPC Section-506) 1 charge related to Cheating and dishonestly inducing delivery of property (IPC Section-420) 1 charge related to Criminal breach of trust by public servant, or by banker, merchant or agent (IPC Section-409)</p>

क्र०सं०	विधायकों का विवरण	आईपीसी का संक्षिप्त विवरण/अधिनियमों का विवरण जो विधायक के अयोग्यता का कारण बन सकता है
	<p>Party:BJP Cases (Charges Framed)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IPC Sections - , Other Details - Sec. 180(A), 147, 174(A) Rly Act. Harihar Rly. Out Post Cr.No.93/2011, C.C.No.397/2011, Court taking Cognizance-JMFC Court, HVR, Cognizance Date-20-06-2011, Framed Court-JMFC Court, Haveri, Framed Date-8-11-2011 2. IPC Sections - 197,198, 420, 409 , Other Details - Sec.13(1) (d) & Prevention of Corruption Act, 1988, Haveri Lokayukta P.S.Cr.No.10/12, Spl. SVC No.12/2013, Framed Court-Haveri Lokayukta Court, Framed Date-20-06-2011 3. IPC Sections - 506, 504, 143, 147, 149, 171F , Other Details - Haveri PS Crime No.64/13, CC.No.111/2013, Haveri, Charges Framed Court-JMFC Court Haveri, Charges Framed Date-30-10-2012 4. IPC Sections - 354B, 506, 504, 143, 147, 149, 323, 324 , Other Details - Byadgi PS Crime No.35/15 C.C.No.329/2015, Court taking Cognizance-Bydagi JMFC, Charges Framed Court- JMFC Court Byadgi, Charges Framed Date - 09-09-2015 	<p>1 charge related to Punishment for undue influence or personation at an election (IPC Section-171F) 1 charge related to Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means (IPC Section-324) 2 charges related to Intentional insult with intent to provoke breach of the peace (IPC Section-504) 2 charges related to Punishment for Rioting (IPC Section-147) 1 charge related to Issuing or signing false certificate (IPC Section-197) 1 charge related to Using as true a certificate known to be false (IPC Section-198)</p>
19	<p>Name:Dinakar Keshav Shetty District: Uttara Kannada Constituency: Kumta Party:BJP Cases (Charges Framed)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IPC Sections - 506, 34, 504, 323, 324 , Other Details - Kumta Police Station, C.R. no. 244/2014, Cognizance court - JMFC Kumta, CC no. 387/2015, Cognizance date 12.06.2015, Framed Court- JMFC Kumta, Framed Date - 29.10.2015 	<p>1 charge related to Punishment for criminal intimidation (IPC Section-506) 1 charge related to Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means (IPC Section-324) 1 charge related to Intentional insult with intent to provoke breach of the peace (IPC Section-504)</p>
20	<p>Name:Narayanagowda District: Mandya Constituency: Krishnarajpet : Bye Election On 05-12-2019 Party:BJP Cases (Charges Framed)</p>	<p>1 charge related to Punishment for undue influence or personation at an election (IPC Section-171F)</p>

क्र०सं०	विधायकों का विवरण	आईपीसी का संक्षिप्त विवरण/अधिनियमों का विवरण जो विधायक के अयोग्यता का कारण बन सकता है
	1. IPC Sections - 171F , Other Details - Case No. 654/2019, Date of Charges Framed : 11.10.2019	
21	<p>Name:Arunkumar Guttur District: Haveri Constituency: Ranebennur : Bye Election On 05-12-2019 Party:BJP Cases (Charges Framed)</p> <p>1. IPC Sections - 353, 504, 506, 149 , Other Details - Haveri Rural Police Station, Crime No. 17/2018, Court Name- JMFC Haveri, Case No. 545/18 is currently transferred to Bangalore Special Court, Framed Date 10.07.2018</p> <p>2. IPC Sections - 379, Other Details - Section 21 MDR Act, Mundargi Police Station, Gadag District, Crime No. 139/2017, Court Name- District and Session Court Gadag, Case No. SC 194/2017, Framed Date 30.11.2017</p>	<p>1 charge related to Punishment for criminal intimidation (IPC Section-506) 1 charge related to Punishment for theft (IPC Section-379) 1 charges related to Intentional insult with intent to provoke breach of the peace (IPC Section-504) 1 charge related to Assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty (IPC Section-353)</p>
22	<p>Name:Sharanu Salagar District: Bidar Constituency: Basavakalyan : Bye Election On 17-04-2021 Party:BJP Cases (Charges Framed)</p> <p>1. IPC Sections - 143, 147, 148, 323, 326, 504, 506, 114, 149 , Other Details - FIR No.448/2018, CC.No.436/19, Cr.No.51/2018, Brahmur P.S. Kalaburagi, Court Name-IV Addl. C.J.(J.D.) & JMFC Gulbarga, Framed Date-10/03/2018</p> <p>2. IPC Sections - 504, 506, 147, 353, 114, 149 , Other Details - FIR No.309/2018, CC.No.618/18, Cr.No.94/2018, Narona P.S. Tq. Aland, Court Name-I Addl. C.J.(JD) & JMFC Aland, Framed Date-04/07/2018</p>	<p>2 charges related to Punishment for criminal intimidation (IPC Section-506) 1 charge related to Voluntarily causing grievous hurt by dangerous weapons or means (IPC Section-326) 2 charges related to Punishment for Rioting (IPC Section-147) 2 charges related to Intentional insult with intent to provoke breach of the peace (IPC Section-504) 2 charges related to Abettor present when offence is committed (IPC Section-114) 1 charge related to Rioting, armed with deadly weapon (IPC Section-148) 1 charge related to Assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty (IPC Section-353)</p>
23	<p>Name:Yashvanthrayagouda Patil District: Bijapur Constituency: Indi</p>	<p>2 charges related to Punishment for criminal intimidation (IPC Section-506) 2 charges related to Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means (IPC Section-324) 3 charges related to Punishment for Rioting (IPC Section-147)</p>

क्र०सं०	विधायकों का विवरण	आईपीसी का संक्षिप्त विवरण/अधिनियमों का विवरण जो विधायक के अयोग्यता का कारण बन सकता है
	<p>Party:INC Cases (Charges Framed)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IPC Sections - 143, 147, 148, 336, 355, 341, 427, 504, 506, 149 , Other Details - Karnataka State, Vijayapura Dist.Indi, Indi Taluk No-16/2007 CC.No. 58/2007, Cognizance Court & Charges Framed Court: Honourable Civil Court & First Class-Indi, Charges Framed Date 13-1-2007 & No: 06, Appeal Dated on 27-11-2017. 2. IPC Sections - 143, 147, 336, 355, 353, 324, 504, 506, 149, Other Details - Karnataka State, Vijayapura Dist.Indi, Indi Taluk no. 18/2007 CC.No.441/2007, Cognizance Court & Charges Framed Court: Honourable Civil Court & First Class-Indi, Charges Framed Date 13-1-2007 & no: 10, Appeal Dated on 27-11-2017. 3. IPC Sections - 143, 147, 148, 323, 324, 504, 149, Other Details - Karnataka State, Vijayapura Dist.Indi, Indi Taluk no. 02/2007 CC.No.488/2007, Cognizance Court & Charges Framed Court: Honourable Civil Court & First Class-Indi., Charges Framed Date 2-1-2007 & No: 12, Appeal Dated on 27-11-2017. 	<p>3 charges related to Intentional insult with intent to provoke breach of the peace (IPC Section-504)</p> <p>2 charges related to Rioting, armed with deadly weapon (IPC Section-148)</p> <p>2 charges related to Assault or criminal force with intent to dishonour person, otherwise than on grave provocation (IPC Section-355)</p> <p>1 charge related to Mischief causing damage to the amount of fifty rupees (IPC Section-427)</p> <p>1 charge related to Assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty (IPC Section-353)</p>
24	<p>Name:B.k.sangameshwara. District: Shimoga Constituency: Bhadravathi Party:INC Cases (Charges Framed)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IPC Sections - 143,147,323,324,504,186,353,506,149 , Other Details - C.C.NO-1518/2016, COGNIZANCE COURT NAME-2nd ADDITIONAL COURT, J.M.F.C , PLACE-BHADRAVATHI, FRAMED COURT NAME-2nd ADDITIONAL COURT,J.M.F.C ,PLACE-BHADRAVATHI 2. IPC Sections - , Other Details - Section-7H, 123 RP Act C.C.NO-275/2010 COGNIZANCE COURT NAME-2nd ADDITIONAL COURT,J.M.F.C ,PLACE-BHADRAVATHI FRAMED COURT NAME-2nd ADDITIONAL COURT,J.M.F.C ,PLACE-BHADRAVATHI 	<p>1 charge related to Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means (IPC Section-324)</p> <p>1 charge related to Punishment for criminal intimidation (IPC Section-506)</p> <p>1 charge related to Punishment for Rioting (IPC Section-147)</p> <p>1 charge related to Intentional insult with intent to provoke breach of the peace (IPC Section-504)</p> <p>1 charge related to Assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty (IPC Section-353)</p>
25	<p>Name:Ranganath H D District: Tumkur</p>	<p>1 charge related to Punishment for criminal breach of trust (IPC Section-406)</p> <p>1 charge related to Cheating and dishonestly inducing delivery of property (IPC Section-420)</p>

क्र०सं०	विधायकों का विवरण	आईपीसी का संक्षिप्त विवरण/अधिनियमों का विवरण जो विधायक के अयोग्यता का कारण बन सकता है
	<p>Constituency: Kunigal Party:INC Cases (Charges Framed)</p> <p>1. IPC Sections - 406, 420, 34 , Other Details - FIR No. 201/2004, Palarivattom Police Station, Kochin, Kerala State, Court taking Cognizance- Judicial First Class Magistrate Court I Ernakulam, Cognizance date. 26.09.2005, Court which framed charge- Judicial First Class Magistrate Court I Ernakulam, CC No. 2867/05, Date of charge framed- 31.10.2005</p>	
26	<p>Name:K.y. Nanjegowda District: Kolar Constituency: Malur Party:INC Cases (Charges Framed)</p> <p>1. IPC Sections - 143, 145, 147, 188, 427, 435, 149 , Other Details - Crime No. 108/2008 Malur Police Station Kolar(Dt.), Karnataka, Cognizance Court Principal JMFC at Malur CC No. 117/09, Date of cognizance 20.02.09, Court which framed the charge 2nd Additional C.J. and JMFC, Framed date 01.04.2016</p>	<p>1 charge related to Mischief by destroying or moving, etc., a land- mark fixed by public authority Mischief by fire or explosive substance with intent to cause damage to amount of one hundred or (in case of agricultural produce) ten rupees (IPC Section-435) 1 charge related to Joining or continuing in unlawful assembly, knowing it has been commanded to disperse (IPC Section-145) 1 charge related to Punishment for Rioting (IPC Section-147) 1 charge related to Mischief causing damage to the amount of fifty rupees (IPC Section-427)</p>
27	<p>Name:Bheema Naik L B P District: Bellary Constituency: Hagaribommanahalli Party:INC Cases (Charges Framed)</p> <p>1. IPC Sections - 504, 143, 147, 447, 323, 114, 117, 506, 149 , Other Details - Bellary Dist Mariyamanahalli Taluk, Karnataka State, Crime No:69/2016, Charges Framed Date: 03/05/2016, Appeal Detail- Dated 14-03-2018, Last Details Submitted in Court on Date:05/04/2018</p>	<p>1 charge related to Punishment for criminal intimidation (IPC Section-506) 1 charge related to Intentional insult with intent to provoke breach of the peace (IPC Section-504) 1 charge related to Punishment for Rioting (IPC Section-147) 1 charge related to Abettor present when offence is committed (IPC Section-114) 1 charge related to Abetting commission of offence by the public or by more than ten persons (IPC Section-117)</p>

क्र०सं०	विधायकों का विवरण	आईपीसी का संक्षिप्त विवरण/अधिनियमों का विवरण जो विधायक के अयोग्यता का कारण बन सकता है
28	<p>Name:Sharath Kumar Bachegowda District: Bangalore Rural Constituency: Hosakote : Bye Election On 05-12-2019 Party:IND Cases (Charges Framed)</p> <p>1. IPC Sections - 143, 147, 188, 341, 353, 149 , Other Details - Hosakote Police Station, Hosakote Town, Bangalore Rural District, FIR No. 0213/2019, Court Name- Principal Civil Judge & JMFC Court Hosakote Bangalore, CC No. 1347/2019, Framed Date 01.07.2019</p>	<p>1 charge related to Punishment for Rioting (IPC Section-147) 1 charge related to Assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty (IPC Section-353)</p>
29	<p>Name:D.c.thammanna District: Mandya Constituency: Maddur Party:JD(S) Cases (Charges Framed)</p> <p>1. IPC Sections - 143, 145, 146, 147, 323, 427, 448, 188, 149 , Other Details - Section 2(B) of Destruction and Loss of Property Act 1981, Crime No. 255/2008, FIR No. 575/2008, C.C.No. 380/2009, Mandya West Police Station, Mandya Karnataka State, Court taking Cognizance- Addl. Civil Judge (Junior Division) and JMFC Mandya, Date of Cognizance- 23.03.2009, Court which framed charge- Addl. CJM (JD & JMFC Mandya), Date of charge framed- 20.02.2018, The Complainant filed an application U/S 323 of CRPC</p>	<p>1 charge related to Joining or continuing in unlawful assembly, knowing it has been commanded to disperse (IPC Section-145) 1 charge related to Rioting (IPC Section-146) 1 charge related to Punishment for Rioting (IPC Section-147) 1 charge related to Mischief causing damage to the amount of fifty rupees (IPC Section-427)</p>
30	<p>Name:Dr.k.annadani District: Mandya Constituency: Malavalli Party:JD(S) Cases (Charges Framed)</p> <p>1. IPC Sections - 171E, 188, 34 , Other Details - Halaguru Police Station, CC No.279/2014, Court taking Cognizance- Prime Civil Court, Malavalli, Charge</p>	<p>1 charge related to Punishment for bribery (IPC Section-171E) 1 charge related to Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means (IPC Section-324) 1 charge related to Punishment for criminal intimidation (IPC Section-506) 1 charge related to Punishment for Rioting (IPC Section-147) 1 charge related to Rioting, armed with deadly weapon (IPC Section-148) 1 charge related to Intentional insult with intent to provoke breach of the peace (IPC Section-504)</p>

क्र०सं०	विधायकों का विवरण	आईपीसी का संक्षिप्त विवरण/अधिनियमों का विवरण जो विधायक के अयोग्यता का कारण बन सकता है
	<p>Framed Court- Prime Civil Court, Malavalli, Framed Date-30/4/2013, Appeal Detail- C.C.No.279/2014, given the stay order by the High Court at Bangalore</p> <p>2. IPC Sections - 143, 147, 148, 504, 323, 324, 506, 149 , Other Details - Halaguru Police Station, CC No.1098/2017, Court taking Cognizance-Prime Civil Court, Malavalli, Charge Framed Court- Prime Civil Court, Malavalli, Framed Date-01/6/2015</p> <p>3. IPC Sections - , Other Details - Sec. LIU/S4 (1) & (3) Rule (3), Labour Manager, CC.No.908/2014, Court taking Cognizance-Prime Civil Court, Malavalli, Charge Framed Court- Prime Civil Court, Malavalli, Framed Date-25/3/2014</p>	
31	<p>Name:M Srinivasa District: Mandya Constituency: Mandya Party:JD(S) Cases (Charges Framed)</p> <p>1. IPC Sections - 405, 406, 420, 463, 465, 468, 120B , Other Details - Sec. 482 Criminal Procedure Act & Sec. 13(1)(D) 13(1)(E) 13(2) The Suppression Corruption Act, P.C.R.No. 01/2011, Cr.No.6/12, Date 24-8-2012, Court Name-Dist. Sessions Court and Lokayuktha Court, Cognizance has not been taken, Framed Date-24-8-2012, Appeal Detail- Honorable Karnataka High Court, Bangalore, Criminal Petition No.5415/2012, and Criminal Petition No. 5886/2012, Lokayutha Court, Date 20-8-2012, P.C.R NO 1/2011, Case has been cancelled and Sent to Lokayutha Court, Case has been sent to CBI for Investigation and Case is under Investigation</p>	<p>1 charge related to Punishment for criminal breach of trust (IPC Section-406) 1 charge related to Cheating and dishonestly inducing delivery of property (IPC Section-420) 1 charge related to Forgery for purpose of cheating (IPC Section-468) 1 charge related to Punishment for forgery (IPC Section-465) 1 charge related to Punishment of criminal conspiracy (IPC Section-120B)</p>
32	<p>Name:Nagangouda District:Yadgir Constituency: Gurmitkal Party:JD(S) Cases (Charges Framed)</p> <p>1. IPC Sections - 188, 34 , Other Details - Sec. 127 (A) R.P. Act, Posted for 313, Crime No.52/2013, C.C.No.241/2013, P.S.-Gurumitkal Vs Nagangouda & another,</p>	<p>1 charge related to Punishment for bribery (IPC Section-171E)</p>

क्र०सं०	विधायकों का विवरण	आईपीसी का संक्षिप्त विवरण/अधिनियमों का विवरण जो विधायक के अयोग्यता का कारण बन सकता है
	<p>Cognizance Court-JMFC Court at Yadgiri, Framed Date-15-4-2013, Framed Court-JMFC Court at Yadgiri</p> <p>2. IPC Sections - 171E , Other Details - Sec. 7 of the Prevention of Religions Misuses Act, 1988, Cr.No.136/2018, P.S.-Nagangouda & Manager Khasamath, Cognizance Court-JMFC Court at Yadgiri, Framed Court-07-04-2018, Framed Date-JMFC Court at Yadgiri</p>	

ADR Association for Democratic Reforms

myneta.info National Election Watch

**Association for Democratic Reforms and
National Election Watch present**

THE UPGRADED
MYNETA APP



DOWNLOAD TODAY!

And be a part of our **#MeraVoteMeraDesh** Campaign



GET IT ON
Google Play

Scan the QR code to download

Visit our website:
www.adrindia.org
www.myneta.info

एडीआर को दान करें

राज्य विधानसभा चुनावों के लिए हमारे #मेरावोटमेरादेश अभियान का समर्थन करने के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। इस अभियान का उद्देश्य राजनीतिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को खत्म करना, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की जानकारी के अधिक प्रसार के माध्यम से मतदाताओं को सशक्त बनाना है। आप निम्नलिखित क्यूआर कोड का उपयोग करके हमें दान कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट के लिंक पर जा सकते हैं।



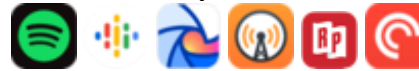
एडीआर स्पीक्स पॉडकास्ट

एडीआर स्पीक्स चुनावी और राजनीतिक सुधारों से संबंधित मुद्दों पर एक पॉडकास्ट श्रृंखला है। एडीआर उम्मीदवारों के पृष्ठभूमि विवरण, राजनीतिक दलों की आय के स्रोतों, चुनावी खर्च, चुनावी बॉन्ड आदि का विश्लेषण करता है। इन एपिसोड में, एडीआर आम जनता की समझ और पहुंच के लिए अपनी रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों का विश्लेषण करता है, जिससे वे एक सूचित विकल्प बनाने में सक्षम होते हैं। एडीआर के पॉडकास्ट में भारत की लोकतांत्रिक राजनीति से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञों, शोधार्थियों, सार्वजनिक बुद्धिजीवियों, पूर्व चुनाव अधिकारियों आदि के साथ चर्चा की जाएगी। एडीआर वेबसाइट पर एपिसोड तक जाने के लिए कृपया आइकन दबाएं।



Listen to Our Podcast on
 Anchor®

Other platforms





To Get Information About Candidates/Parties/MPs/MLAs/Corporators/PILs in courts

Journalist Helpline no: **8010394248**

Subscribe to ADR on **WhatsApp**
for updates: **7840067840**

Visit: **www.myneta.info, www.adrindia.org**

Email: **adr@adrindia.org**

To contact ADR State Partners, visit:
https://adrindia.org/about-adr/state-coordinators

Social Media



/myneta.info



/adr.new



@adrspeaks



/adrspeaks



/adrspeaks

<https://www.linkedin.com/company/association-for-democratic-reforms/>

Our Websites

www.adrindia.org

Provides detailed analytical reports of Lok Sabha, State Assemblies, local body elections & financial reports of political parties & ongoing PILs in courts

www.myneta.info

Provides full information of criminal cases, asset, liability and education details declared by candidates in the self sworn affidavits

Android Apps

Myneta: The criminal, financial, educational & other background information self declared by candidates in their affidavits during elections is now available on your mobile phones.

Election Watch Reporter: This app provides a tool to the citizens to capture violations of election related laws & the code of conduct.

Both the applications are available on Google Play Store

Office Address

Association for Democratic Reforms
T-95, CL House, Second Floor,
Near Gulmohar Commercial Complex, Gautam Nagar,
Landmark: Green Park Metro Station (GN exit),
New Delhi-110 049,
Tel.: 011- 41654200, Fax: 011 - 46094248

सम्पर्क:

कर्नाटक इलेक्शन वॉच

<p>प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री आई.आई.एम बैंगलोर फाउण्डर मेम्बर नेशनल इलेक्शन वॉच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स</p> <p>+91 94483 53285 tsastry@gmail.com</p>	<p>श्री हरीश नरसप्पा स्टेट कोर्डिनेटर</p> <p>harish@dakshindia.org</p>	<p>कात्यायिनी चामराज स्टेट कोर्डिनेटर</p> <p>+91-97318-17177 kchamaraj@gmail.com</p>
--	---	---

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ए.डी.आर)/नेशनल इलेक्शन वॉच (एन.ई.डब्ल्यू)

मीडिया और पत्रकार हैल्पलाईन		+ 91 80103 94248	adr@adrindia.org
मेजर जनरल अनिल वर्मा (सेवानिवृत्त)	हेड/नेशनल कोर्डिनेटर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंव नेशनल इलेक्शन वॉच	+ 91 88264 79910	anilverma@adrindia.org
प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री आई.आई.एम बैंगलोर	फाउण्डर मेम्बर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंव नेशनल इलेक्शन वॉच	+ 91 94483 53285	tsastry@gmail.com
प्रोफेसर जगदीप छोकर सेवानिवृत्त आई.आई.एम अहमदाबाद,	फाउण्डर मेम्बर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंव नेशनल इलेक्शन वॉच		jchhokar@gmail.com

अस्वीकृति

इस रिपोर्ट में दी गयी संपूर्ण जानकारी को एडीआर द्वारा भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट (<https://affidavit.eci.gov.in/>) से प्राप्त किया गया है और सभी जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है। एडीआर किसी भी जानकारी में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करता है, जब तक कि भारतीय चुनाव आयोग से पुष्टि ना हो जाए। एडीआर, भारतीय चुनाव आयोग के अलावा अन्य किसी भी स्रोत या जानकारी का उपयोग नहीं किया करता है। हालांकि एडीआर द्वारा यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए गए हैं कि दी गई जानकारी ईसीआई वेबसाइट में उपलब्ध जानकारी के अनुसार है। इस रिपोर्ट के माध्यम से एडीआर द्वारा दी गई जानकारी में अन्तर होने पर ईसीआई वेबसाइट में दी गयी जानकारी को सही माना जाए और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स, कर्नाटक इलेक्शन वॉच और उनके स्वयंसेवक, इस रिपोर्ट प्रकाशन के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली किसी भी क्षति के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होंगे।

एडीआर, भारत के चुनाव आयोग के साथ जमा किए गए शपथपत्रों से चुनाव के समय उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत की गई पृष्ठभूमि की जानकारी के विश्लेषण और प्रसार में अत्याधिक सावधानी बरतता है। इस तरह की जानकारी का उद्देश्य केवल राजनीति में बढ़ती आपराधिकता, चुनावों में धन के दुरुपयोग में वृद्धि को उजागर करना है ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की व्यवस्था को सुगम बनाया जा सके और मतदाताओं को एक सूचित विकल्प बनाने में सक्षम बनाया जा सके। इसलिए, यह अपेक्षा की जाती है कि इस रिपोर्ट का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति एडीआर द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा का उपयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरतेगा। एडीआर डेटा में किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल, परिवर्तन, समझने में असमर्थता, गलत व्याख्या या हेरफेर के लिए जिम्मेदार नहीं है जिससे किसी विशेष राजनीतिक दल या राजनेता या उम्मीदवार को निशाना बनाया जा सके।